Need to expedite the work of Ferozepur-Patti-Amritsar rail track

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): आदरणीय उपसभापति जी, मैं आज श्री अमृतसर साहब और पंजाब के विषय में बात करना चाहता हूँ। पंजाब वह शहर और स्टेट है, जिन्होंने हमेशा देश के लिए सुरक्षा कवच का काम किया है। यह वह स्टेट है, जहां के लोग पार्टिशन के समय झुलसे। कोई भी जंग हुई, तो पंजाब के लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाईं, चाहे पड़ोसी देश द्वारा देश पर आतंकवाद का हमला हुआ, तो पंजाब ने उसका डटकर मुकाबला किया, उसका मुंह-तोड़ जवाब दिया और उसका खात्मा किया, पर मैं आज जिस विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह यह है कि रेलवे के एक निर्णय में पंजाब को न्याय नहीं मिला। रेलवे का एक निर्णय बहुत दिनों से लंबित है। जहां हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, लेकिन एक नेचुरल रेलवे कॉरिडोर अमृतसर, पंजाब, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को कनेक्ट करने के लिए मिल रहा है, इसके लिए केवल 25.74 किलोमीटर का रेलवे लिंक बनाना पड़ेगा। ऐसा करने से यह नेचुरल फ्रेट कॉरिडोर पंजाब को मिलेगा, इसके साथ ही साथ यह इन सारे स्टेट्स को भी कनेक्ट करेगा। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, जो व्यापार के लिए एक बॉर्डर है। पंजाब को यह एक disadvantage भी है कि यह एक बॉर्डर स्टेट है। उसको आक्रमण झेलने पड़ते हैं और end point के कारण फ्रेट की भी दिक्कत रहती है। इसलिए पंजाब की योजनाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वहां मखू-पट्टी योजना, रेलवे लिंक की बहुत पुरानी योजना है और मैं यह कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि ट्रांसपोर्ट माफिया की connivance से यह प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माफिया को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। पंजाब के इसी एरिया से 20 हजार टन चावल कांडला पोर्ट तक जाता है। पंजाब के जो इंडिस्ट्रयल प्रोडक्ट्स हैं, वे बड़ी संख्या में जाते हैं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां से 3,000 वैगंस रोज आती हैं, 300 बोरियां सीमेन्ट और जिप्सम की होती हैं। उसके लिए यह लिंक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इससे संबंधित दुखद घटना सुना रहा हूँ कि आज से छः-सात साल पहले वर्ष 2013-14 में 147 करोड़ का बजट रखा गया, फिर वर्ष 2014-15 में 10 लाख का बजट रखा गया। मैं एनडीए सरकार को इसके लिए धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इसे सीरियसली लिया और वर्ष 2015-16 में 20 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया, उसके बाद वर्ष 2016-17 के बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यहां पर आदरणीय रेल मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज तक वह कार्य आरंभ क्यों नहीं हुआ? *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. ...(*Interruptions*)... Time over. ...(*Interruptions*)... Shri Narendra Budania. ...(*Interruptions*)... Time over. It is not going on record. ...(*Interruptions*)... Shri Narendra Budania. ...(*Interruptions*)...

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

---

*Not recorded.

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती अम्बिका सोनी (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब): सर, ऑनरेबल मेम्बर ने जो यह विषय उठाया है, यह बहुत ही important है और यह पंजाब के लोगों से जुड़ा हुआ है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you associating? ...(*Interruptions*)... You are supporting. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रताप सिंह बाजवा: हम इससे एसोसिएट करते हैं। **...(व्यवधान)...**

Reduction in irrigated area of Kumbharam Arya lift canal

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान): सर, मैं राजस्थान की इंदिरा गांधी केनाल के विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी केनाल है। इस केनाल ने राजस्थान का नक्शा बदल दिया, इस केनाल ने उन लोगों तक सिंचाई और पीने के लिए पानी पहुँचाया, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। सर, आज मैं यह बात बड़े ही स्वाभिमान से कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजस्थान की जनता कभी भूल नहीं सकती। यह केनाल राजस्थान के रेगिस्तान को ही नहीं, बल्कि शेखावाटी को भी पानी उपलब्ध कराती है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please...(*Interruptions*)... Your time will be lost. Address the Chair. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र बुढानिया: सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस केनाल से पांच लिफ्ट केनाल निकली हैं, जिनमें से सबसे बड़ी लिफ्ट केनाल, चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट केनाल है। मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि वे हमारी सभा के सदस्य रहे हैं और आज उनका जन्म दिन भी है।

महोदय, इस लिफ्ट केनाल के लिए 2.40 लाख हेक्टेयर सिंचित एरिया स्वीकृत हुआ था, लेकिन वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको 2.40 लाख हेक्टेयर से घटाकर 1.622 लाख हेक्टेयर कर दिया, जिससे लाखों किसानों को नुकसान हुआ है। वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लिफ्ट केनाल के निर्माण कार्य को बन्द कर दिया। महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो उसे ये बन्द दिखाते हैं, दूसरी तरफ वर्ष 2008 के चुनाव में 9 माइनर्स के टेंडर निकलते हैं और चुनाव के बाद उन टेंडर्स के बारे में बता दिया जाता है कि ये टेंडर्स तो फर्जी हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और उन 9 माइनर्स के लिए जो टेंडर्स हुए हैं, उनका काम स्टार्ट हो। ये 9 माइनर्स जिनके टेंडर्स हुए थे, उनके नाम मैं बताना चाहता हूँ— सरदार शहर डिस्ट्रिब्यूटरी 14 किलोमीटर, धीरवास माइनर, डूंगरसिंहपुरा माइनर, देवगढ़ माइनर, बांय माइनर, तारानगर व तारानगर सब माइनर। ये बहुत बड़ी माइनर्स हैं, जिनका काम पुनः प्रारंभ होना चाहिए। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ उसमें पानी की कोई कमी नहीं है। उस केनाल में इतना पानी है कि जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि बहुत बड़े रेगिस्तानी एरियाज़